International Journal of Research in all Subjects in Multi Languages [Author: अनिल कुमार] I.F. 9.457

Vol. 14, Issue: 08, August 2026
(IJRSML) ISSN (P): 2321 - 2853

सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारतीय भाषाओं, स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक सहभागिता की भूमिका

अनिल कुमार
शोधार्थी
हेमवती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय
श्रीनगर, गढ़वाल – 246174
ORCID ID: https://orcid.org/0009-0001-3498-6395

सारांश— संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य (Sustainable Development Goals-SDGs) 2030 का एजेंडा वैश्विक स्तर पर गरीबी उन्मूलन, शिक्षा, स्वास्थ्य, जलवायु कार्रवाई और सामाजिक समता जैसे सत्रह व्यापक लक्ष्यों को समाहित करता है। भारत जैसे भाषिक एवं सांस्कृतिक रूप से अत्यंत विविध देश में इन लक्ष्यों की प्राप्ति केवल केंद्रीकृत तकनीकी हस्तक्षेपों से संभव नहीं है, बल्कि इसके लिए भारतीय भाषाओं, पारंपरिक स्थानीय ज्ञान-प्रणालियों और तल-स्तरीय सामुदायिक सहभागिता का समावेशन अनिवार्य है। प्रस्तुत शोधपत्र द्वितीयक स्रोतों पर आधारित एक विश्लेषणात्मक अध्ययन है, जो यह जाँचता है कि किस प्रकार भारतीय भाषाएँ ज्ञान के लोकतंत्रीकरण का माध्यम बनती हैं, स्थानीय एवं आदिवासी ज्ञान-प्रणालियाँ पारिस्थितिक स्थिरता में योगदान करती हैं, तथा सामुदायिक सहभागिता विकास कार्यक्रमों की स्थायित्व-क्षमता को सुदृढ़ करती है। अध्ययन राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के बहुभाषिकता संबंधी प्रावधानों, आदिवासी समुदायों पर केंद्रित अनुभवजन्य साहित्य तथा संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक दस्तावेज़ों की समीक्षा करते हुए यह निष्कर्ष प्रस्तुत करता है कि "स्थानीयकृत सतत विकास" का मॉडल भारत के लिए सर्वाधिक उपयुक्त एवं प्रभावी मार्ग है।

कीवर्ड— सतत विकास लक्ष्य, भारतीय भाषाएँ, स्थानीय ज्ञान, आदिवासी ज्ञान-प्रणाली, सामुदायिक सहभागिता, बहुभाषिकता, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020

परिचय

सतत विकास का प्रश्न मूलतः यह है कि आर्थिक प्रगति, सामाजिक समता और पर्यावरणीय संतुलन को किस प्रकार एक साथ साधा जाए। संयुक्त राष्ट्र के 2030 एजेंडे के अंतर्गत निर्धारित सत्रह सतत विकास लक्ष्य इस त्रिआयामी संतुलन को साधने का वैश्विक ढाँचा प्रस्तुत करते हैं। किंतु इन लक्ष्यों का क्रियान्वयन प्रायः एक समरूप, ऊपर से नीचे (top-down) तकनीकी मॉडल के रूप में किया जाता रहा है, जो स्थानीय सांस्कृतिक-भाषिक संदर्भों की उपेक्षा करता है। भारत, जहाँ बाईस अनुसूचित भाषाएँ, एक हज़ार छह सौ से अधिक मातृभाषाएँ और आठ प्रतिशत से अधिक जनजातीय जनसंख्या निवास करती है, इस चुनौती का एक विशिष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है।

भारतीय भाषाएँ केवल संप्रेषण का माध्यम नहीं हैं, बल्कि वे सदियों से संचित पारंपरिक पारिस्थितिक ज्ञान, कृषि-पद्धतियों, जल-प्रबंधन तकनीकों और सामुदायिक शासन-प्रणालियों की संवाहक भी रही हैं। जब विकास कार्यक्रम स्थानीय भाषा और स्थानीय ज्ञान को दरकिनार करते हुए क्रियान्वित किए जाते हैं, तो वे प्रायः समुदाय की वास्तविक आवश्यकताओं से कट जाते हैं और उनकी स्थायित्व-क्षमता क्षीण हो जाती है। इसके विपरीत, जहाँ स्थानीय भाषा में संवाद, पारंपरिक ज्ञान का सम्मान और समुदाय की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की जाती है, वहाँ विकास कार्यक्रम अधिक प्रभावी, समावेशी और दीर्घकालिक रूप से टिकाऊ सिद्ध होते हैं।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 ने इस दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम उठाते हुए मातृभाषा एवं क्षेत्रीय भाषा को शिक्षा के आधारभूत माध्यम के रूप में प्रतिष्ठापित किया है। इस पृष्ठभूमि में प्रस्तुत अध्ययन भारतीय भाषाओं, स्थानीय ज्ञान-प्रणालियों और सामुदायिक सहभागिता के अंतर्संबंध का विश्लेषण करते हुए यह स्थापित करने का प्रयास करता है कि सतत विकास लक्ष्यों की सच्ची प्राप्ति भारत की भाषिक-सांस्कृतिक विविधता को हाशिये पर रखकर नहीं, अपितु उसे केंद्र में रखकर ही संभव है।

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

साहित्य समीक्षा

स्थानीय एवं आदिवासी ज्ञान-प्रणालियों (Indigenous Knowledge Systems) तथा सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्संबंध पर अंतरराष्ट्रीय एवं भारतीय साहित्य में पर्याप्त कार्य हुआ है। Dei, Anane-Donkor, Dzandza, Peasah तथा Puttick (2025) द्वारा किए गए एक व्यवस्थित समीक्षा अध्ययन ने स्थानीय ज्ञान की विशेषताओं को स्थानीयता, सामुदायिक स्वामित्व, अंतर-पीढ़ीगत हस्तांतरण, समग्रतावादी दृष्टिकोण और अधिकांशतः अनौपचारिक (tacit) प्रकृति के रूप में परिभाषित किया है। इस अध्ययन में यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया गया कि कृषि एवं खाद्य सुरक्षा से संबंधित लक्ष्यों में स्थानीय ज्ञान कृषि-पारिस्थितिकी, मिश्रित खेती और बीज-संरक्षण को बढ़ावा देकर गरीबी एवं भूख के विरुद्ध सामुदायिक प्रतिरोध-क्षमता को सुदृढ़ करता है।

भारतीय संदर्भ में, ScienceDirect में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारत की जनजातीय समुदायों की पारंपरिक प्रथाओं का स्कोपस डेटाबेस-आधारित विश्लेषण करते हुए यह दर्शाया कि भारत की आठ दशमलव छह प्रतिशत जनजातीय जनसंख्या के पास संचित विशाल स्थानीय ज्ञान-भंडार है, जिसका समुचित पहचान, अंगीकरण और मुख्यधारा में समावेशन कृषि उत्पादकता में गिरावट, जैव-विविधता क्षरण, जल-संकट और प्रदूषण जैसी सामाजिक चुनौतियों के सतत समाधान प्रस्तुत करने की क्षमता रखता है। इस अध्ययन ने जनजातीय समुदायों के सामाजिक-आर्थिक स्तर को राष्ट्रीय संकेतक ढाँचे (National Indicator Framework) से जोड़ते हुए नीतिगत सुझाव भी प्रस्तुत किए।

Bansal (2024) द्वारा *Global Business and Organizational Excellence* में प्रकाशित एक समेकित समीक्षा (integrative review) ने आदिवासी समुदायों के सतत विकास लक्ष्यों में योगदान का विश्लेषण करते हुए छह विषयगत क्षेत्रों — अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी, आजीविका, सामाजिक-जनसांख्यिकीय कारक, सतत विकास, तथा राजनीति-नीति-साझेदारी — की पहचान की। इस अध्ययन में यह भी उल्लेखनीय है कि भारत के संदर्भ में आदिवासी समुदायों और उनके ज्ञान को सतत विकास के व्यावहारिक समाधान के रूप में देखने वाले अध्ययन अभी भी अपेक्षाकृत सीमित संख्या में हैं, जो एक स्पष्ट अनुसंधान-अंतराल को इंगित करता है।

2026 में *International Journal of Novel Research and Development* में प्रकाशित एक अध्ययन ने भारतीय ज्ञान-प्रणालियों (Indian Knowledge Systems) को राष्ट्र-निर्माण प्रक्रियाओं से जोड़ते हुए यह तर्क प्रस्तुत किया कि स्वदेशी ज्ञान को आधुनिक नीति एवं वैज्ञानिक ढाँचों के साथ एकीकृत करके भारत ऐसे विकास-पथ अभिव्यक्त कर सकता है जो वैश्विक स्तर पर प्रासंगिक होने के साथ-साथ स्थानीय रूप से भी सुदृढ़ हों। इस अध्ययन ने विशेष रूप से विकेंद्रीकृत एवं सतत संसाधन-प्रशासन की दिशा में स्वदेशी कृषि-पद्धतियों, जल-प्रबंधन प्रणालियों और वन-संरक्षण रणनीतियों की भूमिका को रेखांकित किया, जो जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ जल और जैव-विविधता संरक्षण से संबंधित लक्ष्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संरेखित हैं।

भाषा के प्रश्न पर, UNICEF इंडिया की एक रिपोर्ट स्पष्ट रूप से यह प्रतिपादित करती है कि बच्चे तब सर्वोत्तम रूप से सीखते हैं जब उन्हें उनकी मातृभाषा में शिक्षा दी जाती है। इस रिपोर्ट के अनुसार राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 बहुभाषिकता और परिचित भाषा के उपयोग को कम-से-कम कक्षा पाँच तक, किंतु आदर्शतः कक्षा आठ और उससे आगे तक, प्राथमिकता देती है। रिपोर्ट में छत्तीसगढ़ एवं राजस्थान के भाषा-मानचित्रण (language mapping) पहलों का उल्लेख करते हुए यह बताया गया कि प्रभावी क्रियान्वयन हेतु विविध हितधारकों के निरंतर प्रयास आवश्यक हैं।

भाषा-नीति के आलोचनात्मक विश्लेषण पर केंद्रित एक शोधपत्र ने यह उजागर किया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 पहली बार प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा को शिक्षा के माध्यम के रूप में प्रस्तुत करती है, तथा नीति के पैराग्राफ 4.11 से 4.22 तक "बहुभाषिकता" शीर्षक के अंतर्गत भाषा संबंधी सभी प्रासंगिक पहलुओं को सम्मिलित किया गया है। इस अध्ययन ने यह भी तर्क दिया कि पाठ्यक्रम में अनेक क्षेत्रीय भाषाओं का समावेशन निश्चित रूप से भारत की लुप्तप्राय भाषाओं के संरक्षण में सहायक सिद्ध होगा।

करियर्स360 में प्रकाशित एनसीईआरटी के एक प्रोफ़ेसर के लेख के अनुसार, भारत में 2001 की जनगणना अनुसार पाँच भाषा-परिवारों से संबंधित एक हज़ार छह सौ बावन भाषाएँ बोली जाती हैं, जबकि 2011 की जनगणना एक सौ बाईस भाषाओं और दो सौ चौंतीस मातृभाषाओं को सूचीबद्ध करती है। इस विशाल भाषिक विविधता के बावजूद, उच्च शिक्षा संस्थानों के अधिकांश भाग में अंग्रेज़ी माध्यम की प्रधानता जनजातीय, अल्पसंख्यक एवं लघु भाषाओं के बोलने वालों को दोहरी असुविधा में डालती है — एक ओर प्रमुख राज्य-भाषा से, दूसरी ओर अंग्रेज़ी भाषा से।

समग्र रूप से साहित्य यह प्रदर्शित करता है कि भारतीय भाषाएँ, स्थानीय ज्ञान-प्रणालियाँ और सामुदायिक सहभागिता परस्पर अन्तर्ग्रथित तत्व हैं, जो मिलकर सतत विकास के "स्थानीयकृत" (localized) एवं "सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक" (culturally relevant) मॉडल का निर्माण करते हैं।

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

तालिका 1: प्रमुख अध्ययनों का तुलनात्मक सारांश

अध्ययन/स्रोत	केंद्र-बिंदु	प्रमुख निष्कर्ष
Dei et al. (2025), *Sage Open*	स्थानीय ज्ञान की विशेषताएँ	कृषि, स्वास्थ्य एवं संसाधन-प्रबंधन में SDG योगदान
ScienceDirect अध्ययन (2019)	भारतीय जनजातीय समुदाय	पारंपरिक ज्ञान का SDG संकेतकों से संरेखण
Bansal (2024), *GBOE, Wiley*	आदिवासी समुदाय एवं SDG	छह विषयगत क्षेत्र; भारत-केंद्रित शोध-अंतराल
IJNRD (2026)	भारतीय ज्ञान-प्रणाली एवं राष्ट्र-निर्माण	विकेंद्रीकृत संसाधन-प्रशासन, जलवायु-संरेखण
UNICEF इंडिया रिपोर्ट	मातृभाषा शिक्षा	बेहतर अधिगम, राज्य-स्तरीय भाषा-मानचित्रण पहल
भाषा-नीति आलोचनात्मक विश्लेषण	NEP 2020 भाषा-प्रावधान	मातृभाषा माध्यम, लुप्तप्राय भाषाओं का संरक्षण

शोध समस्या

उपर्युक्त समीक्षा से स्पष्ट होता है कि यद्यपि स्थानीय ज्ञान-प्रणालियों और सतत विकास लक्ष्यों के अंतर्संबंध पर वैश्विक साहित्य विकसित हो रहा है, भारत-विशिष्ट संदर्भ में भाषा, स्थानीय ज्ञान और सामुदायिक सहभागिता — इन तीनों तत्वों को एक समेकित विश्लेषणात्मक ढाँचे में जोड़ने वाले अध्ययन अपेक्षाकृत सीमित हैं। अधिकांश अध्ययन इन तीन आयामों को पृथक-पृथक रूप में संबोधित करते हैं, जबकि व्यवहार में ये तीनों एक-दूसरे पर अन्योन्याश्रित रूप से निर्भर करते हैं।

शोध उद्देश्य

तालिका 2: शोध उद्देश्य

क्रम	उद्देश्य
1	सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में भारतीय भाषाओं की भूमिका का विश्लेषण करना
2	स्थानीय एवं आदिवासी ज्ञान-प्रणालियों के पारिस्थितिक एवं सामाजिक योगदान की पहचान करना
3	सामुदायिक सहभागिता और विकास-कार्यक्रमों की स्थायित्व-क्षमता के अंतर्संबंध की जाँच करना
4	नीति-निर्माण हेतु स्थानीयकृत सतत विकास मॉडल के लिए व्यावहारिक सुझाव प्रस्तुत करना

शोध प्रश्न

- भारतीय भाषाएँ सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित ज्ञान के प्रसार एवं क्रियान्वयन में किस प्रकार योगदान करती हैं?
- स्थानीय एवं आदिवासी ज्ञान-प्रणालियाँ किन विशिष्ट सतत विकास लक्ष्यों के साथ सर्वाधिक संरेखित हैं?
- सामुदायिक सहभागिता के अभाव अथवा उपस्थिति का विकास-कार्यक्रमों की स्थायित्व-क्षमता पर क्या प्रभाव पड़ता है?

शोध पद्धति

प्रस्तुत अध्ययन गुणात्मक, विवरणात्मक एवं विश्लेषणात्मक शोध-अभिकल्प पर आधारित है। इसमें प्राथमिक आँकड़ों का संग्रह नहीं किया गया है, अपितु द्वितीयक स्रोतों — सहकर्मी-समीक्षित शोध-पत्रिकाओं, संयुक्त राष्ट्र के आधिकारिक दस्तावेज़ों, राष्ट्रीय नीति-दस्तावेज़ों (विशेषतः राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020) तथा संस्थागत रिपोर्टों — का विषयगत विश्लेषण किया गया है। स्रोत-चयन के मानदंड में भारतीय अथवा दक्षिण एशियाई संदर्भ, हाल की प्रासंगिकता तथा स्रोत की शैक्षणिक विश्वसनीयता को प्राथमिकता दी गई। एकत्रित सामग्री का वर्गीकरण तीन विषयगत श्रेणियों — भाषा, स्थानीय ज्ञान, तथा सामुदायिक सहभागिता — के अंतर्गत किया गया है।

विश्लेषण एवं विवेचना

भारतीय भाषाओं की भूमिका

भाषा किसी भी विकास-हस्तक्षेप की सफलता का प्रथम एवं सर्वाधिक मौलिक निर्धारक तत्व है। जब कोई सरकारी योजना, स्वास्थ्य-अभियान अथवा कृषि-परामर्श स्थानीय भाषा में संप्रेषित नहीं किया जाता, तो लक्षित समुदाय तक उसकी वास्तविक पहुँच सीमित रह जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का "त्रि-भाषा सूत्र" (Three-Language Formula) इसी समस्या के समाधान की दिशा में एक महत्वपूर्ण नीतिगत प्रयास है। नीति यह अनुशंसा करती है कि जहाँ भी संभव हो, कम-से-कम कक्षा पाँच तक, और आदर्श रूप से कक्षा आठ तक, शिक्षा का माध्यम मातृभाषा अथवा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। यह प्रावधान सीधे तौर पर सतत विकास लक्ष्य चार — समावेशी एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा — से संरेखित है, क्योंकि यह भाषिक रूप से हाशिए पर पड़े जनजातीय एवं अल्पसंख्यक समुदायों के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तक समान पहुँच प्रदान करने का प्रयास करता है।

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

स्थानीय ज्ञान-प्रणालियाँ और पारिस्थितिक स्थिरता

भारत की जनजातीय एवं ग्रामीण समुदायों की पारंपरिक ज्ञान-प्रणालियाँ सदियों की अनुभवजन्य समझ पर आधारित हैं। जल-संचयन की पारंपरिक तकनीकें, मिश्रित खेती, बीज-संरक्षण की स्थानीय पद्धतियाँ, तथा वन-संसाधनों के सामुदायिक प्रबंधन की प्रणालियाँ — ये सभी आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी अत्यंत प्रभावी सिद्ध हुई हैं। यह ज्ञान विशेष रूप से जलवायु कार्रवाई, स्वच्छ जल एवं स्वच्छता, तथा भूमि पर जीवन से संबंधित सतत विकास लक्ष्यों के साथ प्रत्यक्ष रूप से संरेखित है।

तालिका 3: स्थानीय ज्ञान-प्रणालियों एवं सतत विकास लक्ष्यों का संरेखण

स्थानीय ज्ञान का क्षेत्र	संबद्ध सतत विकास लक्ष्य	योगदान का स्वरूप
कृषि-पारिस्थितिकी एवं बीज-संरक्षण	गरीबी उन्मूलन, भूख-मुक्ति	खाद्य सुरक्षा एवं कृषि-प्रतिरोध क्षमता
पारंपरिक जल-प्रबंधन प्रणालियाँ	स्वच्छ जल एवं स्वच्छता	विकेंद्रीकृत जल-संसाधन प्रशासन
वन-संरक्षण एवं सामुदायिक वानिकी	भूमि पर जीवन, जलवायु कार्रवाई	जैव-विविधता संरक्षण
पारंपरिक चिकित्सा एवं सामुदायिक स्वास्थ्य प्रणाली	अच्छा स्वास्थ्य एवं कल्याण	स्थानीय स्तर पर सुलभ स्वास्थ्य-सेवा
सामुदायिक भूमि-शासन प्रणालियाँ	असमानता में कमी, सतत नगर एवं समुदाय	समावेशी निर्णय-प्रक्रिया

सामुदायिक सहभागिता की केंद्रीय भूमिका

अनुभवजन्य साक्ष्य यह दर्शाते हैं कि विकास-कार्यक्रम जब समुदाय को निष्क्रिय लाभार्थी के रूप में नहीं, अपितु सक्रिय भागीदार के रूप में सम्मिलित करते हैं, तब वे अधिक स्थायी एवं प्रभावी सिद्ध होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक एवं सामाजिक मामलों के विभाग द्वारा प्रकाशित दस्तावेज़ में यह स्पष्ट रूप से उल्लिखित है कि स्थानीय ज्ञान-धारकों एवं व्यवहारकर्ताओं की सक्रिय भागीदारी अनुसंधान-निरीक्षण, समीक्षा एवं संपादन जैसी शासन-प्रक्रियाओं में सुनिश्चित की जानी चाहिए, ताकि ज्ञान-प्रणालियों की सामुदायिक प्रासंगिकता बनी रहे। इसी प्रकार, संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन ढाँचा सम्मेलन के अंतर्गत स्थापित "स्थानीय समुदाय एवं स्वदेशी जन मंच" (Local Communities and Indigenous Peoples Platform) विशेष रूप से इसी उद्देश्य से डिज़ाइन किया गया है कि जलवायु-नीति निर्माण की प्रक्रियाओं में स्थानीय समुदायों की आवाज़ को सम्मिलित किया जा सके।

भाषा, ज्ञान और सहभागिता का अंतर्संबंध

इन तीनों तत्वों का पारस्परिक संबंध चक्रीय (cyclical) प्रकृति का है। स्थानीय भाषा के अभाव में स्थानीय ज्ञान का अंतर-पीढ़ीगत हस्तांतरण बाधित होता है; स्थानीय ज्ञान के क्षरण से सामुदायिक आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास कम होता है; और कमज़ोर सामुदायिक सहभागिता से विकास-नीतियाँ स्थानीय संदर्भ से कटी रह जाती हैं। इसके विपरीत, जब ये तीनों तत्व सुदृढ़ रूप में परस्पर संबद्ध होते हैं, तो वे एक सुदृढ़ीकरण-चक्र (reinforcing cycle) का निर्माण करते हैं जो सतत विकास की दीर्घकालिक स्थायित्व-क्षमता को सुनिश्चित करता है।

चर्चा

प्रस्तुत विश्लेषण यह स्पष्ट करता है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु एकरूपी, केंद्रीकृत मॉडल पर्याप्त नहीं है। भारत की भाषिक-सांस्कृतिक विविधता को चुनौती के रूप में नहीं, अपितु संसाधन के रूप में देखे जाने की आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का बहुभाषिक दृष्टिकोण इस दिशा में एक सकारात्मक नीतिगत कदम है, किंतु इसके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रशिक्षित शिक्षकों की उपलब्धता, स्थानीय भाषाओं में गुणवत्तापूर्ण शिक्षण-सामग्री का निर्माण, तथा अभिभावकों की अंग्रेज़ी-माध्यम के प्रति प्राथमिकता जैसी व्यावहारिक चुनौतियों का समाधान आवश्यक है।

इसी प्रकार, स्थानीय ज्ञान-प्रणालियों को औपचारिक नीति-ढाँचे में समाहित करते समय यह सुनिश्चित करना आवश्यक है कि यह प्रक्रिया निष्कर्षणवादी (extractive) न बने, अर्थात स्थानीय ज्ञान का उपयोग तो किया जाए, किंतु उसके मूल धारकों — स्थानीय एवं जनजातीय समुदायों — को निर्णय-प्रक्रिया, श्रेय एवं लाभ के वितरण में उचित स्थान न मिले। सच्ची सामुदायिक सहभागिता का अर्थ है समुदाय को अनुसंधान एवं नीति-निर्माण प्रक्रिया में सह-निर्माता (co-creator) के रूप में सम्मिलित करना, न कि केवल सूचना के स्रोत के रूप में।

निष्कर्ष

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).

प्रस्तुत अध्ययन यह स्थापित करता है कि भारत में सतत विकास लक्ष्यों की सार्थक एवं दीर्घकालिक प्राप्ति के लिए भारतीय भाषाएँ, स्थानीय ज्ञान-प्रणालियाँ और सामुदायिक सहभागिता तीन अपरिहार्य स्तंभ हैं। भाषा ज्ञान के लोकतंत्रीकरण का माध्यम है, स्थानीय ज्ञान पारिस्थितिक एवं सामाजिक स्थायित्व का स्रोत है, तथा सामुदायिक सहभागिता विकास-हस्तक्षेपों की प्रासंगिकता एवं स्थायित्व-क्षमता की गारंटी है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सहित हाल की नीतिगत पहलों ने इस दिशा में सकारात्मक संकेत दिए हैं, किंतु इनके प्रभावी क्रियान्वयन हेतु संस्थागत प्रतिबद्धता, संसाधन-आवंटन एवं निरंतर सामुदायिक संलग्नता आवश्यक है।

सुझाव

तालिका 4: नीतिगत सुझाव

क्षेत्र	सुझाव
भाषा नीति	स्थानीय भाषाओं में सतत विकास संबंधी शिक्षण-सामग्री का विकास किया जाए
स्थानीय ज्ञान	जनजातीय एवं ग्रामीण ज्ञान-भंडार का दस्तावेज़ीकरण एवं औपचारिक मान्यता सुनिश्चित की जाए
सामुदायिक सहभागिता	विकास-परियोजनाओं की योजना एवं मूल्यांकन में स्थानीय समुदायों की सह-निर्णायक भूमिका सुनिश्चित की जाए
शिक्षक-प्रशिक्षण	बहुभाषिक शिक्षण हेतु शिक्षकों का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया जाए
अनुसंधान	भाषा, स्थानीय ज्ञान एवं सहभागिता के अंतर्संबंध पर भारत-केंद्रित अनुभवजन्य अध्ययन बढ़ाए जाएँ

अध्ययन की सीमाएँ

प्रस्तुत अध्ययन पूर्णतः द्वितीयक स्रोतों पर आधारित है, अतः इसमें क्षेत्र-स्तरीय अनुभवजन्य आँकड़ों का अभाव है। इसके अतिरिक्त, भारत की अत्यंत विविध भाषिक-सांस्कृतिक संरचना के कारण इस अध्ययन के निष्कर्षों का सामान्यीकरण सभी क्षेत्रों एवं समुदायों पर समान रूप से लागू नहीं किया जा सकता। भविष्य के अध्ययनों में विशिष्ट राज्यों अथवा जनजातीय क्षेत्रों पर केंद्रित क्षेत्र-आधारित शोध की आवश्यकता है।

संदर्भ सूची

1. Dei, D. J., Anane-Donkor, L., Dzandza, P. E., Peasah, T., & Puttick, C. P. (2025). Synthesizing the characteristics and applications of indigenous knowledge for sustainable development: A systematic review. *Sage Open*. https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/21582440251383843
2. Promoting tribal communities and indigenous knowledge as potential solutions for the sustainable development of India (2019). *ScienceDirect*. https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S2211464519301320
3. Bansal, S. (2024). Indigenous communities and sustainable development: A review and research agenda. *Global Business and Organizational Excellence*, Wiley Online Library. https://onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1002/joe.22237
4. Indian Knowledge Systems and Sustainable Development (2026). *International Journal of Novel Research and Development*, 11(1). https://ijnrd.org/papers/IJNRDG001004.pdf
5. United Nations Department of Economic and Social Affairs. *Integrating Indigenous Knowledge Systems in 2030 UN Sustainable Development Goals*. https://sdgs.un.org/partnerships/integrating-indigenous-knowledge-systems-2030-un-sustainable-development-goals
6. UNICEF India. *Children Learn Best When They're Taught in Their Mother Tongue*. https://www.unicef.org/india/stories/children-learn-best-when-theyre-taught-their-mother-tongue
7. Language Policy under NEP 2020 – A Critical Analysis (2024). *ResearchGate*. https://www.researchgate.net/publication/385669499_Language_Policy_under_NEP_2020_-_A_Critical_Analysis
8. Meganathan, R. (2024). NEP 2020 gives a fresh boost to multilingual education in Indian schools. *Careers360*. https://news.careers360.com/nep-2020-fresh-boost-multilingual-schools-three-language-formula-national-education-policy-ncert-professor/amp
9. Government of India (2020). *National Education Policy 2020*. Ministry of Education, New Delhi.

© 2026. This article is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0).